जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

चूरू

Rashtradoot

फोनः- 256906, 256907, फैक्सः- 01562-256908 | वर्षः 16 | संख्याः 140 | प्रभात | चूरू, सोमवार 16 सितम्बर, 2024 | पो. रजि. न. चूरू/084/2019-21 | पृष्ठ 6 | मूल्य 2.50 रु.

अरविन्द केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद छोड़ने की घोषणा की

सुप्रीम कोर्ट से जमानत के बाद दिल्ली में बड़ी सभा में केजरीवाल ने कहा कि मैं दो दिन बाद मुख्यमंत्री पद छोड़ दूँगा

- राजनीतिक क्षेत्रों में यह चर्चा है कि केजरीवाल ने इस कदम से मास्टर स्ट्रोक खेला है या फिर बड़ा जोखिम मोल ले लिया।
- उन्होंने गैर-भाजपा मुख्यमंत्रियों से आग्रह किया कि अगर उन्हें झूठे केस में गिरफ्तार किया जाता है तो वे इस्तीफा नहीं दें, बल्कि जेल से सरकार चलाये।

नई दिल्ली, 15 सितंबर। रविवार को अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद छोड़ने की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि वे अगले दो दिनों के भीतर दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली की रद्द हो चुकी शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में जमानत दिए जाने के दो दिन बाद केजरीवाल ने यह घोषणा की। छह महीने बाद जेल से रिहा होने के बाद दिल्ली के मु.मंत्री ने पहली बड़ी सभा को संबोधित करते हुए यह घोषणा की।

राजनीतिक हल्कों में पूछा जा रहा कि केजरीवाल की यह घोषणा क्या दिल्ली के विधानसभा चुनाव में जाने से पहले राजधानी की जनता की सहानुभूति बटोरने की रणनीति है? क्या उनका यह कदम उन्हें खुद को जनता के सामने बेदाग साबित करने में कारगर होगा? यह प्रश्न भी पूछा जा रहा है कि केजरीवाल ने यह कदम उठाकर राजनीति का मास्टरस्ट्रोक लगाया है, या एक बहुत बड़ा जोखिम मोल ले लिया है?

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि, उन्हें कानून की अदालत में न्याय मिला है, लेकिन अब वे जनता की अदालत में न्याय चाहते हैं। उन्होंने कहा, "दो दिन बाद मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। जब तक जनता अपना फैसला नहीं सुना देती, मैं उस कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। दिल्ली में चुनाव होने में अभी कई महीने बाकी हैं। मुझे कानूनी अदालत से न्याय मिला, अब मुझे जनता की अदालत से न्याय मिलेगा। मैं जनता के आदेश के बाद ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठूंगा।" उन्होंने कहा, "मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं कि केजरीवाल निर्दोष है या दोषी? अगर मैंने काम किया है, तो मुझे वोट दें।"

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए केजरीवाल ने गैर-भाजपा मुख्यमंत्रियों से अपील की कि अगर उन पर केस दर्ज किए जाते हैं तो वे जेल से इस्तीफा न दें। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि, "वे गैर-भाजपा मुख्यमंत्रियों के खिलाफ झूठे केस दर्ज करते हैं। अगर उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, तो मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वे इस्तीफा न दें बल्कि जेल से सरकार चलाएं।"

केजरीवाल ने कहा कि, उन्होंने पहले इस्तीफा नहीं दिया क्योंकि वे लोकतंत्र के लिए लड़ना चाहते थे। उन्होंने कहा, "मैंने (गिरफ्तारी के बाद) इस्तीफा नहीं दिया क्योंकि मैं लोकतंत्र का सम्मान करता हूं और मेरे लिए संविधान सर्वोच्च है।"

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी के लिए अगला मुख्यमंत्री चुनने के लिए अगले दो दिनों के भीतर दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 60 विधायकों की बैठक होगी। इसके बाद वे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे।

उन्होंने कहा, "फरवरी में दिल्ली में चुनाव होने हैं। मैं मांग करता हूं कि नवंबर में महाराष्ट्र चुनाव के साथ ही चुनाव कराए जाएं। चुनाव होने तक पार्टी से कोई और मुख्यमंत्री होगा। अगले 2-3 दिनों में विधायकों की बैठक होगी, जिसमें अगले मुख्यमंत्री पर फैसला किया जाएगा।"

इस बात से संकेत मिलता है कि आम आदमी पार्टी ने राजधानी में चुनाव से पहले लोगों से जुड़ने के लिए बड़े पैमाने पर संपर्क अभियान की योजना बनाई है। केजरीवाल के अलावा, उनके पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, जो कि शराब नीति केस में जमानत पर हैं, इस अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

कहा जा रहा है कि केजरीवाल का यह आश्चर्यजनक कदम उल्टा भी पड़ सकता है। उन्होंने साफ संकेत दिया है और मनीष सिसोदिया ने भी कहा है कि वे तभी पद पर लौटेंगे जब जनता उनके पक्ष में फैसला सुनाएगी। इसका मतलब है कि आप के दो शीर्ष नेता मुख्यमंत्री पद की दौड़ में नहीं हैं और पार्टी को चुनाव तक अपने अन्य प्रमुख चेहरों में से किसी एक को मुख्यमंत्री पद के लिए चुनना होगा। कुछ महीनों के लिए मुख्यमंत्री चुनने से अक्सर सत्ता को लेकर संघर्ष होने लगता है और बड़े पैमाने पर नेताओं के बाहर निकलने के हालात भी बन जाते हैं। जैसा कि बिहार और झारखंड में हुआ।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मणिपुर में पांच दिन और बंद रहेगा इन्टरनैट

इंफाल, 15 सितंबर। मणिपुर सरकार ने रविवार को राज्य में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध को पांच दिन और बढ़ाकर 20 सितंबर तक कर दिया। राज्य में इंटरनेट प्रतिबंध 10 सितंबर से लागू है। हालांकि ब्रॉडबैंड सेवाएं उन लोगों को प्रदान की गई है जिन्होंने इस बात का वचन दिया था कि वे वाईफाई का उपयोग नहीं करेंगे। आज सुबह पांच बजे से दोपहर 12 बजे तक घाटी के पांच जिलों में कर्फ्यू में ढील दी गई। ग्यारह पहाड़ी जिलों में कर्फ्यू नहीं है।

कथित कुकी उग्रवादियों ने ड्रोन, मिसाइलों और अन्य अत्याधुनिक हथियारों का उपयोग करके नए हमले किए। इन हमलों को रोकने में सरकार की विफलता के विरोध में छात्रों ने आंदोलन शुरू कर दिया है।

बजरी से भरे हुए डंपर ने कार को कुचला, 6 की मौत

बूंदी, 15 सितम्बर (निसं)। बूंदी जिले में रविवार सुबह हिंडोली में नेशनल हाईवे 52 पर बजरी से भरे हुए डंपर ने एक कार को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो

- मध्य प्रदेश के निवासी खाटूश्याम जी दर्शन के लिए जा रहे थे, जब हिंडौली के पास यह हादसा हुआ।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

चीन में काम कर रही अमेरिकी कम्पनियाँ भारी निराशा के माहौल में हैं

अमेरिका में आधे से ज्यादा बिज़नैस कम्पनियों को विश्वास है कि गत वर्ष की तुलना में बिज़नैस बढ़ेगा

- चीन में काम कर रही अमेरिकी कम्पनियों में केवल 37 प्रतिशत को आशा है कि उनका बिज़नेस बढ़ेगा।
- इस निराशा के वातावरण के कारण 25 प्रतिशत अमेरिकी कम्पनियों ने, चीन में अपना "इन्वैस्टमैंट" घटा दिया है।
- ये आंकड़े शंघाई स्थित अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स तथा चीन के यूरोपियन यूनियन के चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने अपनी-अपनी रिपोर्ट में दिए हैं।
- दो कारण हैं, चीन की इकॉनमी के स्लोडाउन के, एक तरफ तो है चीन व अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव तथा दूसरा कारण है, चीन में कंज़्यूमर गुड्स की मांग उठ नहीं रही, बल्कि लगातार कम हो रही है।
- तनाव के कारण, अमेरिकी बिज़नैस चीन में काम करने को जोखिम भरा मामला मानने लगीं तथा डिमाण्ड में कमी होने से वे यह जोखिम उठाना, चीन में घटती मांग के कारण तुलना में नुकसान का सौदा मानने लगी हैं।

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 15 सितम्बर। चीन में संचालित हो रही अमेरिकी कंपनियाँ अत्यधिक लो प्रॉफिट का सामना कर रही हैं। अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते तनाव और कमज़ोर होती चीन की इकॉनमी के कारण बिज़नैस कॉन्फिडैंस का स्तर बहुत नीचा है।

शंघाई में अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि जिन 306 कंपनियों का सर्वे किया गया उनमें से केवल 66 प्रतिशत कंपनियों ने 2023 में प्रॉफिट दर्शाया। यह, न्यूनतम प्रॉफिट का एतिहासिक रिकॉर्ड है। साथ ही, सर्वे में केवल 47 प्रतिशत कंपनियाँ अगले 5 वर्षों में चीन में बिज़नैस की अपनी संभावनाओं को लेकर आशावादी है, चीन पिछले दो दशकों में आशावाद का यह न्यूनतम स्तर है।

ट्रेड मैन्युफैक्चरिंग को लेकर बीजिंग और वॉशिंगटन के बीच चल रहे विवाद तथा साउथ चाइना सी में चीन के क्षेत्रीय दावों ने वर्तमान वातावरण पैदा किया है। इसके अलावा, चीन की इकॉनमी कमज़ोर उपभोक्ता मांग तथा लगातार बने हुए महंगाई के दबाव से जूझ रही है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि दोनों देशों के बीच तनाव, चीन में कारोबार के लिए प्रमुख चुनौती है। शंघाई में अमेरिकन चेम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडैंट एरिक झांग ने कहा कि जहाँ चीन में बिज़नैस करने के खतरे बढ़ गए हैं। वहीं, कम होती मांग तथा अत्यधिक उत्पादन क्षमता के कारण मार्केट की गति धीमी पड़ रही है। परिणामस्वरूप कई कंपनियाँ अपने निवेश-वियतनाम, मलेशिया साउथ एशिया के अन्य क्षेत्रों

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

प्रयागराज में गंगा-जमुना खतरे के निशान के पास

प्रयागराज,15 सितंबर। पहाड़ों और उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश और केन, बेतवा तथा चंबल नदियों का पानी यहां पहुंचने से तीर्थराज प्रयाग में गंगा और यमुना का जलस्तर धीरे-धीरे खतरे के निशान की ओर बढ़ चला है।

- गत 24 घंटे में विभिन्न स्थानों पर नदियों का जल स्तर 86 सैंटीमीटर से 2.58 मीटर बढ़ा।
- पहाड़ों व उत्तराखंड में लगातार बारिश से तथा केन, बेतवा तथा चंबल नदियों का पानी पहुंचने से स्थिति गंभीर हुई।

दोनों नदियां खतरे के निशान से करीब एक मीटर दूरी पर बह रही हैं।

बाढ़ नियंत्रण कक्ष के आंकडों के अनुसार पिछले 24 घंटों में दोनों नदियों का जलस्तर फाफामऊ में, गंगा 2.58 मीटर, छतनाग में 1.36 मीटर और नैनी

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

समाज के विभिन्न वर्गों ने भारी वर्षा के बीच कोलकाता में विरोध प्रदर्शन किया

कोलकाता दुष्कर्म-हत्याकांड में सी.बी.आई. ने आरोपी पूर्व प्राचार्य घोष तथा थाना प्रभारी को सियालदह अदालत में पेश किया

- पूर्व रक्षा अधिकारियों, सेवानिवृत्त शिक्षकों, अस्पतालों के नर्सिंग स्टाफ ने अलग-अलग रैलियाँ निकालीं।
- सी.बी.आई. ने अदालत में कहा कि दोनों आरोपी घटना के दिन लगातार फोन पर सम्पर्क में थे तथा उन पर सबूतों में छेड़छाड़ व एफ.आई.आर. दर्ज कराने में देरी करने का आरोप है।

कोलकाता, 15 सितंबर। पूर्व रक्षा अधिकारियों, विद्यार्थियों, सेवानिवृत्त शिक्षकों और अस्पतालों के नर्सिंग स्टाफ सहित समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने रविवार को यहां भारी बारिश के बीच प्रदर्शन किया और आर जी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की प्रशिक्षु डॉक्टर के लिए न्याय की मांग की जिनकी नौ अगस्त को बलात्कार के बाद बेरहमी से हत्या कर दी गयी थी।

पुरुलिया सैनिक स्कूलों के पूर्व विद्यार्थियों (जो सेना, भारतीय वायु सेना और भारतीय नौसेना में शीर्ष पदों से सेवानिवृत्त हुए,) ने दक्षिण कोलकाता के जादवपुर से गोल पार्क तक एक रैली निकाली। सेवानिवृत्त रक्षा अधिकारियों में से एक आशीष बनर्जी ने कहा कि वे उच्चतम न्यायालय की सुनवाई के नतीजे को लेकर आशान्वित हैं, लेकिन देश में कानूनी प्रक्रिया में समय लगता है।

कलकत्ता बालिका उच्च विद्यालय के पूर्व शिक्षकों और विद्यार्थियों ने बारिश की परवाह किए बिना मध्य कोलकाता के वेलिंगटन स्क्वायर में अपने स्कूल से उत्तर कोलकाता के श्यामबाजार तक एक विशाल रैली निकाली। पूर्व शिक्षकों में से एक ने कहा कि वे आर जी कर अस्पताल की घटना के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं और साथ ही सरकार को यह भी अपील करना चाहते हैं कि वह अपनी अगली पीढ़ि यों के लिए एक सुरक्षित राज्य सुनिश्चित करें।

विभिन्न अस्पतालों के नर्सिंग कर्मचारी पूर्वी कोलकाता के करुणामयी में एकत्र हुए और सेंट्रल पार्क में डॉक्टरों

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

गहलोत राज में डी.ओ.आई.टी. में 3500 करोड़ के घोटाले हुए- डॉ. किरोड़ी

डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने गृह राज्य मंत्री बेढम से घोटालों की जाँच के लिये एफ.आई.आर. दर्ज कराने की मांग की

- सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के 3500 करोड़ रूपए के घोटाले की शिकायत गहलोत राज में की गई थी, पर, गहलोत सरकार ने ए.सी.बी. की जाँक की इजाज़त नहीं दी थी- डॉ. किरोड़ी
- मंत्री जवाहर सिंह ने बैठक में कहा कि उन्होंने डी.जी.पी. को मामले की जाँच कर कार्यवाही करने को कहा है।

जयपुर, 15 सितम्बर (का.सं.)। डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम को सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग (डीओआईटी) में हुए कथित 3500 हजार करोड़ के घोटालों की शिकायत की है। किरोड़ी मीणा ने रविवार को बेढम के आवास पर पहुँचकर बताया कि गहलोत राज में डिपार्टमैंट ऑफ इन्फॉर्मेशन टैक्नॉलजी (डी.ओ.आई. टी.) में करीब 3500 करोड़ के घोटाले की शिकायत एसीबी में की गई थी, लेकिन गहलोत सरकार ने एसीबी को जांच की इजाज़त नहीं दी।

किरोड़ी ने कहा कि कबाड़ा गहलोत सरकार में हुआ है, लेकिन अब हमारा मौका है। हमारी सरकार है, ऐसे में गृह राज्य मंत्री बेढम से मिलकर इन घोटालों की जांच के लिए एफ.आई.आर. दर्ज करने की मांग करने आया हूं।

इस मुलाकात के बाद मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि सरकार में सीनियर मंत्री किरोड़ीलाल मीणा कांग्रेस राज में हुए घोटाले की जांच करवाने की मांग लेकर आए थे। मैंने डी.जी.पी. को फोन कर कहा है कि इस मामले की जांच कर कार्रवाई करें।

मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा दो महीने पहले पेपर लीक के सबूत लेकर एस.ओ.जी. ऑफिस पहुंचे थे। डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने एस.ओ.जी. के अधिकारियों और आर.पी.एस.सी. चेयरमैन पर बड़े आरोप लगाए थे। उन्होंने एस.ओ.जी. के ए.डी.जी. वी.के. सिंह को तीन भर्ती एग्जाम, आर.ए.एस., रिट और एस.आई. में हुए पेपर लीक के सबूत सौंपे थे। किरोड़ीलाल मीणा ने अपनी शिकायत में डी.ओ.आई.टी. के कई अधिकारियों पर आरोप लगाए। इसमें प्रोजेक्ट अधिकारी दीपशिखा सक्सेना, कुलदीप यादव, वित्त अधिकारी कौशल गुप्ता पर अलग-अलग फर्मों को गलत दस्तावेजों पर करोड़ों रुपए के वर्क ऑर्डर जारी करने का आरोप लगाया।

इसके अलावा उन्होंने अधिकारी आशुतोष देशपांडे और पूर्व अतिरिक्त

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)